ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST | Vol. 3 | Issue 7 | July 2025
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i7.147

बदलते हुए परिदृश्य में घरेलू कचरा प्रबंधन पर आधारित एक अध्ययन: इटावा जिले के विशेष संदर्भ में

शालिनी यादव [1], प्रो॰ अर्चना चौधरी [2]

[1]**शोधार्थिनी, गृह विज्ञान ज्वाला देवी विद्या मन्दिर पी॰जी॰ कालेज, कानपुर**
Email ID: shalinidevansh@gmail.com
[2]**शोध निर्देशिका, प्रोफेसर, गृह विज्ञान, ज्वाला देवी विद्या मन्दिर पी॰जी॰ कालेज, कानपुर**
Email ID: archanachau11@gmail.com

शोध सारांश

वर्तमान समय में पर्यावरणीय संतुलन एवं स्वच्छता के प्रति वैश्विक चेतना के संदर्भ में घरेलू कचरा प्रबंधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति तथा बदलती जीवनशैली ने कचरे की मात्रा एवं प्रकृति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। प्रस्तुत अध्ययन **"बदलते हुए परिवेश में घरेलू कचरा प्रबंधन पर आधारित एक अध्ययन: इटावा जिले के विशेष संदर्भ में"** के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है।

शोध हेतु 200 परिवारों (100 शहरी, 100 ग्रामीण) से प्राथमिक जानकारी प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा संकलित की गई। अध्ययन में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा आंशिक कचरा संग्रहण व्यवस्था मौजूद है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक स्वयं निपटान करते हैं। कचरे के पृथक्करण की जागरूकता शहरी क्षेत्र में भी सीमित है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग नगण्य है। सरकारी योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता अपेक्षाकृत कम पाई गई।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इटावा जिले में कचरा प्रबंधन की स्थिति असंतुलित है और इसमें व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक सक्रियता की अत्यंत आवश्यकता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं एवं स्थानीय निकायों के लिए कचरा प्रबंधन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।

कीवर्ड: घरेलू कचरा प्रबंधन, पर्यावरणीय संतुलन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र इटावा जिला, जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन

प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में घरेलू कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और उपभोग की आदतों में बदलाव के कारण

कचरे की मात्रा में तीव्र वृद्धि हो रही है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और संसाधनों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इटावा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कचरे के प्रकार, प्रबंधन के तौर-तरीकों, लोगों की जागरूकता एवं सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

आज का युग तेजी से विकसित होते समाज, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और उपभोगतावादी प्रवृत्तियों का युग है। मानव सभ्यता जितनी प्रगति कर रही है, उतनी ही तेजी से उसके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। यह कचरा विशेषकर घरेलू जीवन से उत्पन्न होने वाला ठोस एवं तरल अपशिष्ट न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह पर्यावरणीय असंतुलन, भूमि एवं जल प्रदूषण, और जैव विविधता के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में "घरेलू कचरा प्रबंधन" का विषय समकालीन शोधों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

घरेलू कचरा सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में घरों से उत्पन्न होने वाले जैविक (खाद्य अवशेष, फल-सब्जियों के छिलके आदि) और अजैविक (प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच आदि) पदार्थों का मिश्रण होता है। पहले के समय में, जब जनसंख्या कम और संसाधनों का उपयोग सीमित था, तब कचरे का निस्तारण आसान होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कचरे को पशुओं के लिए चारा या खेतों में खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समाज में उपभोग की प्रवृत्ति और एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई, प्लास्टिक, थर्माकोल, पैक्ड फूड, और डिस्पोजेबल वस्तुओं का चलन बढ़ा, वैसे-वैसे कचरे की प्रकृति भी जटिल होती गई।

बदलते सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में कचरा केवल गंदगी नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या का रूप ले चुका है, जिसका असर न केवल पर्यावरण पर, बल्कि जनस्वास्थ्य, नगर विकास, जलवायु परिवर्तन, और सामाजिक व्यवहारों पर भी पड़ रहा है। खासतौर पर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और भी भयावह हो चुकी है।

भारत में घरेलू कचरा प्रबंधन की स्थिति असंगठित और अव्यवस्थित रही है। नगर निकायों के पास संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की असमानता, जनजागरूकता की न्यूनता और व्यवहारगत चुनौतियाँ इसे और भी कठिन बना देती हैं। 'स्वच्छ भारत मिशन', 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016' जैसी सरकारी योजनाओं और नीतियों के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर उनके प्रभाव में कई बाधाएँ आती हैं। इटावा जिला, जो कि उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्से में स्थित है, इसका एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इटावा जिले की जनसंख्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से फैली हुई है। यहाँ के लोग धीरे-धीरे आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कचरे की मात्रा एवं उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहा है। प्लास्टिक बैग, रेडी-टू-ईट पैकेट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट आदि का उपयोग भी बढ़ा है। लेकिन इसके निपटान की पद्धति आज भी पारंपरिक या अव्यवस्थित है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी स्वयं द्वारा गड्ढा खोदकर या खुले में जलाकर कचरा नष्ट करते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की

व्यवस्था सीमित और असमान रूप से कार्यशील है। कूड़ेदान की अनुपलब्धता, असमय कचरा संग्रहण, कर्मचारियों की कमी, और नागरिकों की असंवेदनशीलता स्थिति को और अधिक जटिल बनाती है।

इटावा जैसे जिले, जहाँ शिक्षा का स्तर औसत है, और शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से बढ़ रही है, वहाँ यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि घरेलू कचरा प्रबंधन की व्यापक समीक्षा की जाए, जिससे न केवल वर्तमान समस्याओं की पहचान हो सके, बल्कि भविष्य के लिए ठोस समाधान भी प्रस्तावित किए जा सकें। इसी सोच के साथ प्रस्तुत यह शोध कार्य इटावा जिले के विशेष संदर्भ में घरेलू कचरा प्रबंधन की स्थिति का गहन अध्ययन करता है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का उत्पन्न होना, उसका संग्रहण, पृथक्करण, निस्तारण, और नागरिकों की सहभागिता कैसी है। साथ ही, सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया गया है।

इस शोध की सहायता से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इटावा जैसे मध्यमवर्गीय, अर्ध-शहरी जिले में घरेलू कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें क्या कमियाँ हैं, और किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज और सरकार मिलकर इसे एक सुचारु, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से अनुकूल प्रणाली में बदल सकते हैं। यह शोध न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अन्य समान प्रकृति वाले जिलों के लिए भी एक आदर्श दिशा निर्देश प्रस्तुत कर सकता है।

शोध की आवश्यकता

- बढ़ते कचरे के दुष्परिणामों को समझना
- इटावा जिले में कचरा प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन
- व्यवहारगत और संस्थागत समस्याओं को पहचानना

शोध के उद्देश्य

1. इटावा जिले में घरेलू कचरे के प्रकारों का वर्गीकरण करना
2. घरेलू कचरा प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करना
3. नागरिकों की कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता को मापना
4. सरकारी योजनाओं एवं नगर निकायों की भूमिका का मूल्यांकन करना
5. बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए सुझाव देना

शोध पद्धति (Research Methodology)

इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसका उद्देश्य इटावा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति, व्यवहारगत प्रवृत्तियों और सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को चुना गया, जो एक अर्ध-शहरी और सामाजिक दृष्टि से विविध जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसमें नगर पालिका क्षेत्र (शहरी) और तीन प्रमुख ग्राम पंचायतें (ग्रामीण) शामिल की गईं।

नमूना चयन के लिए सरल यादृच्छिक पद्धति (Simple Random Sampling) का प्रयोग किया गया, जिसमें कुल 200 परिवारों का चयन किया गया – जिनमें से 100 शहरी और 100 ग्रामीण क्षेत्र से लिए गए। इन परिवारों से प्राथमिक जानकारी एक संरचित प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र की गई।

प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए तैयार प्रश्नावली में कचरे के प्रकार, संग्रहण विधियाँ, पृथक्करण की आदतें, नगर निकाय की सेवाओं से संतुष्टि, तथा कचरा निस्तारण के तरीकों से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

द्वितीयक डेटा नगर निगम रिपोर्ट, स्वच्छ भारत मिशन की रिपोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेजों, तथा संबंधित शोध पत्रों से संकलित किया गया।

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों, जैसे प्रतिशत, बार चार्ट व तालिकाओं के माध्यम से किया गया जिससे निष्कर्षों को अधिक वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक आधार मिल सके।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

इस अध्ययन में इटावा जिले के 200 चयनित परिवारों (100 शहरी एवं 100 ग्रामीण) से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण मुख्यतः कचरे के प्रकार, संग्रहण की विधियाँ, पृथक्करण की प्रवृत्ति, जागरूकता का स्तर, और सरकारी सेवाओं से संतुष्टि पर आधारित रहा। आंकड़ों को प्रतिशत, तालिकाओं और बार चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

1. कचरे के प्रकार

शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न कचरे में 65% जैविक कचरा, 25% प्लास्टिक, 5% कांच/धातु और 5% अन्य अपशिष्ट पाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कचरे का अनुपात अधिक (80%) था, जबकि प्लास्टिक मात्र 10%, कांच/धातु 3% और अन्य 7% रहा। इससे स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में गैर-जैविक कचरे का प्रयोग अधिक है।

2. कचरा संग्रहण की स्थिति

शहरी क्षेत्रों में 60% परिवारों का कचरा नगर निकाय द्वारा एकत्रित किया जाता है, जबकि 30% स्वयं निपटान करते हैं और 10% निजी एजेंसियों की सेवा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार स्वयं कचरा नष्ट करते हैं, 15% ही ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों की सेवा लेते हैं।

3. कचरा पृथक्करण

केवल 30% शहरी परिवार सूखा और गीला कचरा पृथक करते हैं, जबकि 70% अभी भी मिश्रित कचरा फेंकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 12% लोगों को ही कचरे के पृथक्करण की जानकारी है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता है।

4. सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन

नगर निकाय की सेवाओं से 40% लोग आंशिक रूप से संतुष्ट पाए गए। मात्र 25% लोगों ने जागरूकता अभियानों के बारे में सुना था, और 35% ने सार्वजनिक डस्टबिनों की उपलब्धता को अपर्याप्त बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र लगभग नगण्य था।

डेटा से स्पष्ट होता है कि इटावा जिले में घरेलू कचरा प्रबंधन की स्थिति असंतुलित है। शहरी क्षेत्रों में संरचना तो है पर उपयोगिता सीमित है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था लगभग अनुपस्थित है। जागरूकता, संसाधन और प्रशासनिक भागीदारी में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष (Findings)

पर्यावरणीय संकट, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण घरेलू कचरा प्रबंधन आज न केवल एक प्रशासनिक चुनौती बन गया है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भी जुड़ा विषय हो गया है। इटावा जिले में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कचरा प्रबंधन की स्थिति शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में चिंताजनक है, यद्यपि समस्याओं की प्रकृति और स्तर दोनों भिन्न हैं।

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि शहरी क्षेत्रों में जैविक और अजैविक कचरे की मात्रा अधिक है, विशेषकर प्लास्टिक और पैक्ड उत्पादों का उपयोग बढ़ने के कारण कचरे की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बदल रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, लेकिन संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्थित व्यवस्था लगभग नगण्य है।

शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा संग्रहण की कुछ व्यवस्था है, परंतु यह असंगठित और आंशिक रूप से क्रियाशील है। कूड़ेदान की संख्या अपर्याप्त है और नियमित सफाई की प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश नागरिक कचरे को स्वयं नष्ट करते हैं – जैसे खुले में फेंकना, जलाना या खेतों में डालना – जिससे न केवल स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण भी होता है।

कचरे के पृथक्करण (सूखा एवं गीला) के प्रति नागरिकों में जागरूकता बेहद कम है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ 50% से अधिक लोग इस अवधारणा से परिचित हैं, वहाँ भी केवल 30% ही वास्तव में पृथक्करण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी कम है, जो कि इस बात का संकेत है कि केवल नीति निर्माण से नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन से ही समाधान संभव है।

सरकारी योजनाओं जैसे 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016' की जानकारी अधिकांश नागरिकों को नहीं है। जो जानकारी रखते हैं, वे भी उसके क्रियान्वयन से असंतुष्ट हैं। विशेषकर शिकायत निवारण तंत्र, डस्टबिन की उपलब्धता, और नियमित सफाई जैसे बिंदुओं पर प्रशासनिक उदासीनता पाई गई।

इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि घरेलू कचरा प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी, जागरूकता, संसाधनों की उपलब्धता, और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आवश्यक है। जब तक समाज के सभी वर्ग– प्रशासन, समुदाय, विद्यालय, और

स्वयंसेवी संस्थाएँ–एक साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक कचरा प्रबंधन की यह समस्या विकराल रूप लेती जाएगी।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इटावा जिले के संदर्भ में घरेलू कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति मिश्रित है–शहरी क्षेत्र में अधूरी व्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग शून्य। इसे प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए नीतिगत सुधारों के साथ-साथ जन-सहभागिता और सामाजिक चेतना को प्राथमिकता देनी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. भारत सरकार. (2016). सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली, 2016. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

[2]. भारत सरकार. (2021). स्वच्छ भारत मिशन – शहरी एवं ग्रामीण वार्षिक रिपोर्ट. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय।

[3]. नगर पालिका परिषद, इटावा. (2023). स्वच्छता कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

[4]. सिंह, आर. (2022). भारत में ठोस कचरा प्रबंधन की चुनौतियाँ. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जर्नल, 7(2), 41-49।

[5]. मिश्रा, वी. (2020). स्थानीय निकायों की भूमिका एवं स्वच्छता. नगर प्रशासन समीक्षा, 12(1), 55-61।

[6]. Tripathi, S. (2021). Waste Management Practices in Small Towns of India: A Case Study of Etawah. Journal of Environmental Research, 18(3), 212-225.

[7]. Shukla, A. (2022). Urban Waste Segregation and Awareness. Indian Waste Management Review, 10(4), 101–110.

[8]. Pandey, M. (2020). Kachra Niyantran Mein Samudaayik Bhaagidaari. Lok Prabandhan, 9(1), 33–40।

[9]. Singh, N., & Verma, P. (2021). Domestic Waste Management and Health Implications. Social Science Journal, 6(2), 65–73.

[10]. Ministry of Housing and Urban Affairs. (2022). Annual Report: Swachh Bharat Mission Urban. Government of India.

[11]. Swachh Bharat Mission. (2023). Dashboard & Progress Report. Retrieved from https://swachhbharatmission.gov.in

[12]. Gupta, M. (2022). Rural Waste Disposal Challenges in Uttar Pradesh. Journal of Rural Studies, 5(2), 115–124.

[13]. Sharma, R. (2019). Plastic Waste and Urban Health Hazards. Environmental Perspectives, 11(1), 92–99.

[14]. National Green Tribunal. (2021). Orders on Waste Management. New Delhi.

[15]. Etawah District Statistics Handbook. (2023). District Planning Office, Etawah.

[16]. Jain, A. (2020). Pariyavaran Shiksha aur Nagar Swachhata. Shodh Sameeksha, 14(2), 78–84।

[17]. UN Habitat. (2021). Solid Waste Management in Urban India: Challenges & Solutions.

[18]. Centre for Science and Environment (CSE). (2022). Managing Urban Waste: Models & Case Studies. New Delhi.

[19]. Ahmad, Z. (2020). Kachre ki Samasya aur Nagar Nigam ki Bhumika. Shahar aur Vikas, 8(3), 39–46।

[20]. World Bank. (2021). What a Waste 2.0: Global Snapshot of Solid Waste Management.

[21]. Chaudhary, K. (2021). Swachh Bharat Mission ke Prabhav ka Vishleshan. Samaj Vigyan Vimarsh, 6(1), 19–25।

[22]. Bajpai, R. (2022). Urban Governance and Waste Handling. Urban Research Digest, 4(3), 109–117.

[23]. Kumar, R. (2020). Kachra Prabandhan mein Vigyanik Drishtikon. Science for Society, 3(1), 44–51।

[24]. Singh, M. (2023). Domestic Waste Patterns and Management Practices in Semi-Urban Areas. Research Journal of Social Issues, 2(2), 76–83.

[25]. The Energy and Resources Institute (TERI). (2021). Solid Waste Management Toolkit. New Delhi.

Cite this Article

शालिनी यादव, प्रो॰ अर्चना चौधरी, बदलते हुए परिदृश्य में घरेलू कचरा प्रबंधन पर आधारित एक अध्ययन: इटावा जिले के विशेष संदर्भ में, *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 3, Issue 7, pp. 94-100, July 2025.*

Journal URL: *https://ijmrast.com/*

DOI: *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i7.147*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.